



रॉबर्ट वाड्रा का बयान: देश भर से प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की मांग के बाद उनके पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी है कि ऐसी आवाज़ें देशभर से उठ रही हैं। वाड्रा ने कहा कि कई समूह और लोग चाहते हैं कि प्रियंका आगे आएँ और नेतृत्व करें, और कुछ लोगों ने यह तक कहा है कि उन्हें खुद राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन फिलहाल पार्टी को लोगों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी

कहा कि प्रियंका का राजनीति में उज्ज्वल भविष्य है और उन्होंने अपने परिवार के वरिष्ठ नेताओं से कई चीज़ें सीखी हैं। इमरान मसूद ने कहा है कि यदि प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वह बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा जैसे मामलों पर इंदिरा गांधी की तरह निर्णायक प्रतिक्रिया दे सकती हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज़ हो गई है। हालाँकि कांग्रेस ने अभी तक

पार्टी के लिए आधिकारिक प्रधानमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन वाड्रा के स्पष्ट समर्थन और मांगों के बीच नेतृत्व और रणनीति पर बहस उभर रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस प्रकार के बयान चुनावी रणनीति और नेतृत्व संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की है, ताकि पार्टी की छवि मजबूत बन सके और आगामी चुनावों के लिए व्यापक समर्थन जुटाया जा सके।

TOP NEWS | ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके में क्या हुआ था?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके में क्या हुआ था? पूर्व वायुसेना प्रमुख ने किया बड़ा खुलासा

मुंबई | नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) वीआर चौधरी ने मंगलवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान जब पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला किया, तो भारतीय वायुसेना ने भी करारा जवाब देते हुए उसके सबसे अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। चौधरी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई के कारण पाकिस्तान ने मई में चार दिन चले सैन्य संघर्ष के बाद आखिरकार घुटने टेक दिए।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के जवाब में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हमला करने का बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) चौधरी आईआईटी बंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे,



जिसमें पूर्व नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और पूर्व सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त टीमों की साहसिक योजना का नतीजा था। पीओके में 9 आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सात मई

को भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी शिविरों पर हमला किया, जिनमें से दो शिविरों-बहावलपुर और मुर्दिके-पर मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना ने हमला किया। पूर्व वायु सेना प्रमुख ने कहा कि यह पहली बार था, जब भारत इतनी गहराई में गया और एकदम सटीक निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि हमें किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। पाकिस्तानियों ने हमारे सैन्य ठिकानों और नागरिक लक्ष्यों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करके जवाब दिया। उन्होंने उधमपुर में कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया। हमने भारत पर दागे गए हर ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। हालांकि, एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) चौधरी ने कहा कि भारत की एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली इन सभी हमलों को नाकाम करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि हमने भारत पर दागे गए हर ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। हमारे देश में कोई क्षति नहीं हुई। जब वे हमारे ठिकानों को निशाना बना रहे थे, तो स्थिति थोड़ी बेकाबू हो रही थी। जब वे हमारे ठिकानों पर हमला कर रहे थे, तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उनके उन ठिकानों पर हमला करना पड़ा, जहां से उनके विमान और ड्रोन उड़ान भरते थे।

एसआईआर : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल के साथ ही अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 95 लाख नाम हटे



संवाददाता | NEWS AGENCY

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान एवं निकोबार में मंगलवार को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में लगभग 95 लाख मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए। अंडमान एवं निकोबार में 3.10 लाख मतदाताओं में से 64,000 मतदाता, जबकि केरल में 2.78 करोड़ मतदाताओं में से 24.08 लाख लोगों के नाम मसौदा सूची से हटाए गए। छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अनुसार, राज्य में 1,79,043 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 1 प्रतिशत है। सीईओ कार्यालय ने बताया कि 2.12 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 87

प्रतिशत ने अपने गणना प्रपत्र जमा कराए, जो व्यापक सहभागिता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख लोगों के नाम मसौदा सूची से हटाए गए। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। जिन लोगों के नाम मसौदा सूची से हटाए गए हैं, वे अब भी अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और मतदाता पंजीकरण अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। यह कदम मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि आगामी चुनावों में विश्वसनीय मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।



मुंबई एयरपोर्ट विवाद: नाजिया खान के मुस्लिम स्टाफ संबंधी बयान पर इमरान प्रतापगढ़ी ने की कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: मुंबई हवाईअड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस के मुस्लिम कर्मचारियों के खिलाफ विवादित बयान देने वाली भाजपा अल्पसंख्यक नेता नाजिया इलाही खान पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भड़क उठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इंडिगो प्रबंधन से अपने कर्मचारियों के पक्ष में खड़े होने और नाजिया खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

इससे पहले नाजिया खान ने एयरलाइन में मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की संख्या अधिक होने से एयरलाइन प्रबंधन को नियंत्रण रखना चाहिए या भर्तियां बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर “तीन बार मिनी जेहाद” का सामना करना पड़ा।

नाजिया खान ने इंडिगो के मालिकों पर भी आरोप लगाया कि वे “लिबरल हिंदू” होने के नाते कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसे कर्मचारियों की मौजूदगी से यात्रियों को परेशान किया जाता है। इस विवाद ने कार्यस्थल में समानता, सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों को फिर से उजागर कर दिया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और सोशल मीडिया पर आलोचना के बीच इंडिगो प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ गई है।

114 दिन कोमा और किडनी फेल के बाद 5 साल का बच्चा एम्स नागपुर से चमत्कारिक रूप से ठीक होकर घर लौटा



नागपुर: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का परासिया निवासी पांच वर्षीय बच्चा, जो जहरीले कफ सिरप कोल्डड्रिफ के सेवन के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गया था, 114 दिन के कोमा और किडनी फेल होने के बाद एम्स नागपुर से पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। यह बच्चे की उम्र इस तरह की विषाक्तता से ठीक होने वाले सबसे कम उम्र के मामले में आती है।

इस जहरीले कफ सिरप में औद्योगिक रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था, जिसने देशभर में 24 बच्चों की जान ले ली। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में इस पर कड़ी कार्रवाई की गई।

बच्चे को 11 सितंबर को एम्स नागपुर रेफर किया गया। भर्ती होने पर उसकी गुर्दे की

गंभीर विफलता, निम्न रक्तचाप, कई अंगों की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी और लगभग न के बराबर ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्स जैसी गंभीर स्थिति थी। डॉक्टरों ने उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन और आपातकालीन डायलिसिस पर रखा। बाल रोग विभाग की डॉ. मीनाक्षी गिरीश और टीम ने बाल रोग विशेषज्ञ, तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, गुर्दे रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ और पुनर्वास विशेषज्ञ के साथ मिलकर बच्चे का इलाज किया।

माता-पिता ने दिन-रात उसका साथ दिया। उन्होंने निजी अस्पताल में 6 लाख रुपये खर्च किए और सरकारी अस्पताल पर भरोसा रखा। लंबे इलाज के दौरान पिता को नौकरी गंवानी पड़ी, जबकि मां को बड़ी बेटी से दूर रहना पड़ा।

अब बच्चा बोलने, चलने-फिरने और दैनिक गतिविधियों में सक्षम हो गया है। डॉक्टरों ने ऑप्टिक तंत्रिका क्षति और आंशिक दृष्टि वापसी की पुष्टि की। एम्स ने उपचार का खर्च माफ कर दिया। डॉक्टरों ने बच्चे के ठीक होने को चमत्कार करार दिया और कहा कि यह आयु वर्ग का पहला मामला है, जिसमें इतने विषैले पदार्थों के प्रभाव के बाद जीवन बचा।

भारत ने आकाश-एनजी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के यूजर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया

संवाददाता | NEWS AGENCY

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को आकाश-एनजी (Akash Next Generation) एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे इसकी भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रक्रिया और आगे बढ़ गई है। परीक्षणों में मिसाइल ने विभिन्न रेंज और ऊँचाइयों पर हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, जिसमें कम ऊँचाई तथा लंबी दूरी वाले लक्ष्य भी शामिल थे। यह प्रणाली सभी आवश्यक मानकों (PSQR) पर खरी उतरी। DRDO और रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आकाश-एनजी में स्वदेशी RF सीकर, ड्यूल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर, तथा पूरी तरह घरेलू रेडार और C2 सिस्टम लगे हैं, जिससे यह वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। यह मिसाइल प्रणाली हवाई खतरों के खिलाफ सुरक्षा कवच को और सुदृढ़ करेगी और भारतीय वायु सेना तथा सेना के लिए आधुनिक वायु रक्षा तैयारियों को बढ़ाएगी। यूजर परीक्षणों की सफलता इसके आगामी तैनाती के लिए सकारात्मक संकेत है, जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।



शेख हसीना प्रत्यर्पण से लेकर हिंदू की लिंगिंग तक: भारत-बांग्लादेश संबंधों में गंभीर तनाव

नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध हाल के दिनों में तीव्र तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिनके बीच कई राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं ने कूटनीतिक खटास बढ़ा दी है। इस विवाद की शुरुआत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में निर्वासन और उनके प्रत्यर्पण की ढाका सरकार की मांग से हुई, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव का पहला स्तर बन गया। भारत ने स्पष्ट कहा कि वह बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रत्यर्पण को लेकर कोई रुख नहीं अपनाया।

बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति तब और भड़क गई जब विरोध प्रदर्शनों के दौरान

प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो गई, जिससे देश भर में प्रदर्शन और राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो गयी। इसके बाद दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू नागरिक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (लिंगिंग) कर दी गयी, जिससे भारत में व्यापक रोष फैल गया। दास की लिंगिंग और उसके शरीर को आग लगाए जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक नींव पर गंभीर संकट खड़ा किया है।

इन घटनाओं के बाद नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए और कई शहरों में भी विरोध की लहर आई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता

बांग्लादेश को बताई है और उच्चायुक्त को तलब किया गया। दूसरा दबाव बांग्लादेशी पक्ष पर तब आया जब ढाका में भारत विरोधी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों के बीच वीजा सेवाओं के निलंबन जैसे कदम उठाए गए, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक माहौल और जटिल हो गया है।

विश्लेषकों का कहना है कि इन विवादों ने दोस्ताना संबंधों में खटास ला दी है और यदि दोनों पक्ष आपसी संवाद और विश्वास बहाली के उपाय नहीं करते हैं, तो क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को खतरा हो सकता है।



संपादकीय अग्रलेख | महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवाल और लोकतंत्र की कसौटी

संपादकीय... |

महाराष्ट्र में आज, 23 दिसंबर 2025 को जिस मुद्दे ने सबसे अधिक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दिया है, वह है स्थानीय निकाय चुनावों के बाद ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। चुनाव परिणामों के ऐलान के तुरंत बाद सामने आई शिकायतों, जांच और सात कर्मचारियों के निलंबन ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।

21 दिसंबर को हुए नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनावों में जहां कई जगहों पर सत्ताधारी दलों को झटका लगा, वहीं विपक्षी दलों ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। चुनावी हार-जीत के इस सियासी उतार-चढ़ाव के बीच जब ईवीएम में तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक की खबर सामने आई, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि सत्तापक्ष ने इसे सीमित स्तर की प्रशासनिक लापरवाही करार दिया।

प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सात कर्मचारियों को निलंबित करना यह दर्शाता है कि मामले को हल्के में नहीं लिया गया। यह कदम एक ओर जहां जनता के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि क्या चुनाव पूर्व तैयारियों और प्रशिक्षण में कहीं चूक रह गई थी? यदि ईवीएम जैसी संवेदनशील प्रणाली में थोड़ी सी भी लापरवाही होती है, तो उसका सीधा असर लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख पर पड़ता है।

महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सजग राज्य में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे जनता की आकांक्षाओं और भरोसे की अभिव्यक्ति भी होते हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर संदेह की गुंजाइश लोकतंत्र को कमजोर करती है। यह सच है कि अब तक ईवीएम प्रणाली को देश की न्यायपालिका और चुनाव आयोग ने सुरक्षित और भरोसेमंद माना है, लेकिन बार-बार उठने वाले सवाल यह संकेत देते हैं कि जनविश्वास बनाए रखने के लिए तकनीकी मजबूती के साथ-साथ संवाद और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है।

आज की चर्चा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चुनाव परिणामों के बाद राज्य की राजनीति एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। कई नगरपालिकाओं में त्रिशंकु स्थिति, नए गठबंधनों और क्षेत्रीय दलों के उभार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता अब स्थानीय मुद्दों पर अधिक सजग होकर निर्णय ले रहा है। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसी के साथ प्रशासन और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।

संपादकीय दृष्टि से यह समय केवल आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन और राजनीतिक दलों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हों, जिनसे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हों। तकनीकी ऑडिट, कर्मचारियों का बेहतर प्रशिक्षण, और शिकायत निवारण की तेज व पारदर्शी व्यवस्था इस दिशा में ठोस कदम हो सकते हैं।

अंततः लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विश्वास का तंत्र है। यदि जनता का भरोसा डगमगाता है, तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है। महाराष्ट्र में आज उठी ईवीएम से जुड़ी बहस हमें यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र की मजबूती निरंतर सतर्कता, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही संभव है। यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे अहम सीख है।

TOP NEWS | भारत की मदद पर बोलीं श्रीलंकाई एक्सपर्ट

'हीरो' जयशंकर तब आए, जब अपनों ने छोड़ा साथ , भारत की मदद पर बोलीं श्रीलंकाई एक्सपर्ट

कोलंबो: भारत ने श्रीलंका को चक्रवात दिवाह से प्रभावित क्षेत्रों की मदद के तौर पर साढ़े चार सौ मिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कोलंबो में इसकी जानकारी दी है। इस पैकेज में चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए साढ़े तीन सौ मिलियन डॉलर की रियायती ऋण लाइन और 100 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है। इस ऐलान के बाद जयशंकर और भारत की श्रीलंकाई लोग सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं।



श्रीलंका की जानी-मानी पत्रकार जमीला हुसैन ने एक्स पर एस जयशंकर की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, 'हमारे देश में 2022 में जब आर्थिक संकट अपने चरम पर था तो जयशंकर कोलंबो गए और उन लोगों से मिले, जो घंटों तक फ्यूल की लाइनों में लगे थे।

उन्होंने वह किया जो उस समय कोई भी श्रीलंकाई नेता करने को तैयार नहीं था। उन्होंने खुद फ्यूल संकट का जायजा लिया। आज जब हम दिवाह से उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो वह फिर मदद के लिए कोलंबो में हैं। उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन पैकेज के तौर पर 450 मिलियन डॉलर का वादा किया है। भारतीय नेताओं ने श्रीलंकाई लोगों के लिए हमारे अपने लोगों से भी ज्यादा किया है।

पीएम मोदी की चिट्ठी सौंपी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बनकर कोलंबो पहुंचे हैं। जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और उन्हें पीएम मोदी की चिट्ठी भी सौंपी है। कोलंबो में जयशंकर ने कहा कि तूफान दिवाह के बाद यहां संकट के समय भारत के लिए आगे आना स्वाभाविक था।

श्रीलंकाई विदेश मंत्री विजिथा हेराथ के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा, 'मैं यहां राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के लिए एक मैसेज लेकर आया हूं। राष्ट्रपति से मैंने तूफान दिवाह से हुए नुकसान पर डिटेल में बात की। पीएम मोदी का जो लेटर मैंने उनको सौंपा, वह हमारी फर्स्ट रेस्पॉन्डर भूमिका को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज देने का वादा करता है।'

दिवाह में आई भारत से टीम एस जयशंकर ने इस दौरान कहा, 'दिवाह के समय हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रान्त और आईएनएस उदयगिरी कोलंबो में राहत का सामान पहुंचाया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के कई एमआई-17 हेलीकॉप्टर दो हफ्ते तक श्रीलंका में एक्टिव रहे। 80 लोगों की नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टुकड़ी ने भी राहत ऑपरेशन चलाए।

WORLD NEWS | भारतीय वर्कर्स की शरण में पहुंचा रूस

यूक्रेन युद्ध का असर, भारतीय वर्कर्स की शरण में पहुंचा रूस, 2026 में 72,000 को देगा जॉब

मॉस्को: रूस ने भारत के कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बीते चार वर्ष से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस ने लेबर रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए भारत से 72,000 प्रवासियों को लाने की योजना बनाई है। इससे भारतीयों के लिए रूस में काम करने के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा होंगे। रूस और भारत के बीच कामगारों को लेकर हालिया समय में कई समझौते हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के दौरान भी इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में सहमति बनी थी। हालांकि रूस में काम के लिए जाने वाले युवाओं को जबर्न सेना में भेजने के आरोप भी लगे हैं। मोस्कोव्स्की कोम्सोमोलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के लिए रूस ने आधिकारिक विदेशी कामगारों का कोटा 235,000 रखा है।



इसमें भारत को आधिकारिक तौर पर 71,817 का कोटा दिया गया है। हालांकि नई दिल्ली और बॉम्बे के कुछ सूत्रों का कहना है कि यह संख्या पूरे भारत से आने वाले आवेदनों के सामने बहुत कम है। कुछ रिपोर्ट में रूस से 10 लाख तक भारतीयों को वीजा देने का भी दावा किया गया, मंत्रालय ने अवास्तविक बताते हुए खारिज किया है। पुतिन के प्रतिनिधि ने दिए आंकड़े रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि बोरिस टिटोव ने कहा है कि कम से कम 42,000

भारतीय राजधानी मॉस्को और देश के दूसरे बड़े शहरों में आएंगे। टिटोव ने कहा कि वास्तव में कितने लोग होंगे, यह अभी भी पता नहीं है लेकिन उम्मीद है कि यह आंकड़ा 40,000 से कम नहीं होगा।

2026 में 72,000 को देगा जॉब

पुतिन के विशेष प्रतिनिधि ने जारी हुए परमिट के आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में 8,000 भारतीयों को परमिट मिले। साल 2023 में ये संख्या 14,000 और 2024 में बढ़कर 36,000 हो गई। यह दिखाता है कि रूस आने वाले भारतीय कामगारों की संख्या बीते तीन सालों में तेजी से बढ़ी है।

सेना में भरती की चिंता बोरिस टिटोव ने भारतीयों की रूस में काम करने की बढ़ती दिलचस्पी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत लेबर रिसोर्स की कमी को पूरा करने में रूस की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभाशाली हैं। दुबई जैसे शहर को मुख्य रूप से भारतीय मजदूरों और डेवलपर्स ने बनाया है। भारतीयों की चिंता कुछ ऐसी रिपोर्ट बढ़ा रही हैं, जिनमें कहा गया है कि रूसी अधिकारी भारत के साथ लेबर एग्रीमेंट डील का इस्तेमाल करके भारतीयों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में भेज रहे हैं। ऐसे आरोप रूस पर लगाने वाले कई भारतीय हालिया समय में सामने आए हैं।

Top News | बांग्लादेश में हिंसा पर चीन ने तोड़ी चुप्पी,

बांग्लादेश में हिंसा पर चीन ने तोड़ी चुप्पी, चुनाव पर मोहम्मद यूनस को दिया कड़ा संदेश

बीजिंग: चीन ने बांग्लादेश हो रही हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते देश में तय समय पर चुनाव कराने पर जोर दिया है। चीन की ओर से कहा गया है कि वह बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव और स्थिरता के अपने पारंपरिक राजनयिक रुख पर कायम है। चीन का बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देशभर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा की वजह से देश में प्रस्तावित चुनाव के टाले जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। बांग्लादेश में अगले वर्ष 12 फरवरी को चुनाव होना है।

बांग्लादेश की स्थिति पर पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'चीन ने स्पष्ट कहा है कि हम बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू संसदीय चुनाव चाहते हैं। हमारा मानना ​​है कि बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्र महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडों को ठीक से आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखेंगे।' चीन ने तय समय पर चुनाव पर जोर देकर यूनस सरकार को कड़ा संदेश दिया है क्योंकि उन्होंने कई बार इलेक्शन में टालमटोल का रवैया दिखाया है।

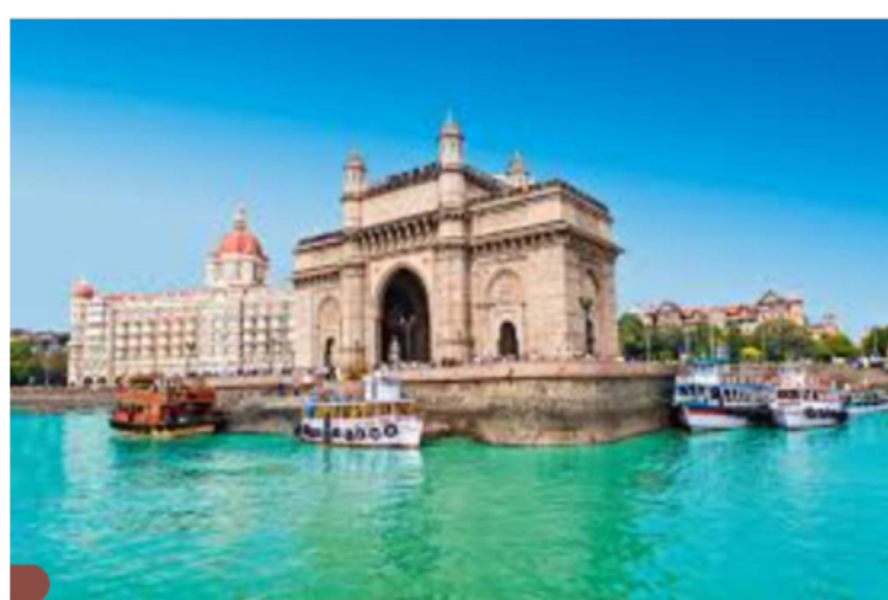
बीजिंग-ढाका संबंध

चीन की नजर बांग्लादेश की स्थिति पर लगी हुई है क्योंकि हालिया वर्षों में उसके संबंध ढाका से काफी बेहतर हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में ढाका के लिए चीन मुख्य आर्थिक और रणनीतिक पार्टनर बनकर उभरा है। खासतौर से मोहम्मद यूनस के सत्ता में आने के बाद से चीन ने आर्थिक के साथ-साथ सैन्य सहयोग भी ढाका से बढ़ाया है।

बांग्लादेश में जारी हिंसा का हवाला देते हुए चुनाव टाले जाने की आशंका कई एक्सपर्ट जता रहे हैं। खालिदा जिया की सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे आमिर खस्रु महमूद चौधरी ने भी यूनस प्रशासन

पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भीड़ के हिंसक विरोध प्रदर्शनों को चुनाव रोकने के 'औजार' के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का शक जताया है।

बांग्लादेश के आगामी चुनाव को टालने पर नाराजगी जताते हुए देश के अहम राजनीतिक दल बीएनपी ने कहा है कि वह इसके पक्ष में नहीं है। बीएनपी ने पहले भी जल्दी से जल्दी चुनाव कराने पर जोर दिया है। बीएनपी नेताओं ने एक बार फिर कहा है कि फरवरी में होने वाले चुनाव का लोगों को इंतजार है। आम लोगों के अलावा उम्मीदवार भी अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Wednesday 24th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 238 , पृष्ठ 04

नवनीत राणा का विवादित बयान: “अगर वे 19 बच्चे करें तो हमें भी कम से कम 4 बच्चे करना चाहिए”



संवाददाता |

बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने जनसंख्या पर एक विवादित बयान देकर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। उन्होंने एक मौलवी के कथित बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति चार पत्नियों के साथ 19 बच्चे पैदा करता है, तो “हिंदुओं को भी कम से कम चार बच्चे पैदा करने चाहिए।” राणा का यह बयान जनसंख्या नियंत्रण और समुदायों के बीच संतुलन

के मुद्दे को लेकर आया है, जिसे सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में कड़ी आलोचना और समर्थन दोनों का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने इसे भड़काऊ और असंवेदनशील बताया, जबकि कुछ समर्थक इसे “संख्या वृद्धि के प्रति चेतावनी” कहा। राणा पहले भी विवादित बोलों के लिए चर्चा में रह चुकी हैं, जिससे यह बयान फिर से सुर्खियों में आया है।

मराठा-कुणबी जातप्रमाणपत्र विवाद: मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र शासन को नोटिस जारी की

नागपुर | 23 दिसंबर 2025: महाराष्ट्र सरकार द्वारा 25 जनवरी 2024 और 2 सितंबर 2025 को जारी किए गए दो शासन निर्णयों (Government Resolution - GR) के खिलाफ एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई है। इन जीआर के माध्यम से मराठा समाज के लोगों को मराठा-कुणबी या कुणबी-मराठा के रूप में जातप्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें ओबीसी (Other Backward Classes) आरक्षण के लाभ प्राप्त हो सकें।

ओबीसी मुक्ती मोर्चा नामक संगठन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उक्त जीआर असंवैधानिक, मनमानी और घटनात्मक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 1 जून 2004 के पुराने आदेश के तहत



मराठा-कुणबी तथा कुणबी-मराठा पहले से ही कुणबी (ओबीसी) उपश्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

नए जीआर के जरिये समूची मराठा जात को अप्रत्यक्ष रूप से ओबीसी लाभ प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ है तथा इससे सामाजिक असंतुलन

और आरक्षण प्रणाली में अन्याय उत्पन्न होने की संभावना है।

याचिका में यह भी उल्लेख है कि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 पहले से ही मराठा समाज को 10% आरक्षण प्रदान करता है।

ऐसे में उसी समुदाय को ओबीसी श्रेणी से भी लाभ देना न्यायालय की पूर्वनिर्णयों और सामाजिक सिद्धांतों के विपरीत है, और इससे आरक्षण की मूल न्यायिक आधारभूत सीमाओं का उल्लंघन होने का खतरा है। नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति मुकुलिका जवळकर और न्यायमूर्ति एम. चांदवानी की संयुक्त पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह मांग भी रखी गई है कि संबंधित शासन निर्णयों को रद्द किया जाए तथा वर्तमान में उनके अमल पर तत्काळ रोक लगाई जाए।

यह मामला महाराष्ट्र में जात प्रमाणपत्र, आरक्षण और सरकारी नीतियों से जुड़े संवेदनशील सामाजिक एवं कानूनी विवादों को फिर से उजागर करता है, जिसका प्रभाव न केवल मराठा समुदाय पर, बल्कि ओबीसी समूहों और अन्य पिछड़ा वर्गों पर भी पड़ सकता है।

Mumbai BMC Election: महाराष्ट्र में मनसे-शिवसेना UBT गठबंधन पर मुहर, ठाकरे ब्रदर्स कल मुंबई में करेंगे ऐलान



मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच गठबंधन हो गया है।

दोनों ठाकरे ब्रदर्स कल यानी 24 दिसंबर को मुंबई में औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि 12 बजे इसका ऐलान होगा। महाराष्ट्र निकाय चुनावों के पहले राउंड के नतीजे आने के बाद अब मुंबई समेत राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव होने हैं। इसके लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे। दोनों भाई राजनीतिक तौर पर 20 साल बाद एक साथ आए हैं। राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर बदलने वाले सियासी समीकरण पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की

अगुवाई वाली शिवसेना की पैनी नजर है। पहले राउंड में लगा है बड़ा झटका महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की झटका लगा है। कांग्रेस का प्रदर्शन जहां संतोषजनक रहा है तो वहीं शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी को झटका लगा है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर एक साथ आए थे। इसके बाद दोनों भाईयों के बीच जमी बर्फ पिघल गई थी। इसके बाद से मनसे और शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन की चर्चा थी।

ठाकरे ब्रदर्स का मिलन

टर्निंग प्वाइंट! महाराष्ट्र में इस टर्निंग प्वाइंट के तौर पर देखा जा रहा है। बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा सीधे दांव पर लगी है। अगर मुंबई में शिवसेना यूबीटी की हार होती है तो उद्धव ठाकरे की राजनीति हैसियत और कमजोर हो जाएगी। राउत की पोस्ट के अनुसार दोनों भाई कल गठबंधन के साथ सीटों के समझौते का ऐलान करेंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज ठाकरे काफी अच्छे वक्ता हैं। ऐसे में जब दोनों भाई मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति की मुश्किल बढ़ सकती है। मुंबई बीएमसी के साथ अन्य महानगरपालिका के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है।

नांदेड में 32 वर्षों बाद 1993-94 बैच के छात्रों का भावनात्मक मिलन समारोह संपन्न

नांदेड स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री निकेतन विद्यालय, दीपक नगर, तरोड़ा (बु.) में वर्ष 1993-94 के कक्षा 10वीं के पूर्व छात्रों का “उत्सव मैत्रीचा” (गेट-टुगेदर) कार्यक्रम 21 दिसंबर को उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लगभग 32 वर्षों बाद आयोजित इस मिलन समारोह में विद्यार्थियों ने अपने शालेय जीवन की खट्टी-मीठी यादों को ताजा किया।

कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के पूजन एवं राष्ट्रगान से की गई। इसके पश्चात सभी पूर्व विद्यार्थियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र का परिचय देते हुए विद्यालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। छात्रों ने विद्यालय के योगदान को सम्मानित करने हेतु स्कूल को जेरॉक्स मशीन भेंट स्वरूप प्रदान की।

इस अवसर पर विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री यशवंत



श्रीनिकेतन हायस्कूल, नांदेड
वर्ग-१० वा इ.स. १९९३-९४

थोरात सर, सेवानिवृत्त शिक्षिका सौ. अरुणा नरवाडे सहित अन्य पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बाद में ईरा हॉल में सभी ने स्नेहभोजन का आनंद लिया। मित्र-मैत्रिणियों द्वारा विभिन्न खेलों और गतिविधियों का आयोजन कर शालेय जीवन की स्मृतियों

को पुनर्जीवित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में नितीन कोंडेकर, विजय खंदारे, मधुकर सावंत, सदानंद देशमुख, मिलिंद नरवाडे, शेख इस्माईल, सारिका कस्तुरे, सरिता देशमुख, वैशाली शिंदे, प्रताप सावंत सहित अनेक पूर्व विद्यार्थियों का योगदान रहा। सूत्रसंचालन वैशाली शिंदे ने किया तथा आभार प्रदर्शन विजय खंदारे ने किया।

बीड: संतोष देशमुख हत्या केस में सभी आरोपियों पर आरोप तय

संवाददाता |

बीड जिला व विशेष सत्र न्यायालय ने मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड तथा अन्य आरोपियों पर आज आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कर दिए हैं। संतोष देशमुख को 9 दिसंबर 2024 को अतिशय क्रूरता से अपहृत कर मौत के घाट उतारा गया था। इस हत्या के पीछे खून से भरी खंडणी मांगने के विरोध का मामला बताया जा रहा है, जिसमें अवादा कंपनी से 2 करोड़ रुपये की मांग का विरोध संतोष ने किया था और इसी वजह से गोलीचालित हत्या की कथित साजिश रची गई थी।

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने मीडिया से कहा कि न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं, और अब अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को होगी। उन्होंने बताया कि वकीलों द्वारा सुनवाई को टालने के कई प्रयास किए गए, लेकिन आज न्यायालय ने आरोप तय कर मामले को आगे बढ़ाया। इस फैसले के बाद प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जिससे दोषियों के खिलाफ सबूतों पर आगे की सुनवाई तेज होगी। इस घटना ने महाराष्ट्र में सरकारी प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों की सुरक्षा व कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।



सुप्रिया सुळे ने स्पष्ट किया: 26 दिसंबर को अलग-अलग NCP समुदाय के बीच कोई औपचारिक विलय नहीं

महाराष्ट्र की राजनीति में दो अलग-अलग NCP (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी)-समूहों के बीच 26 दिसंबर को संभावित समेकन की चर्चा तेज है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। Sharad Pawar-नियंत्रित NCP (SP) की नेता और सांसद सुप्रिया सुळे ने स्पष्ट कहा है कि अभी तक दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह का औपचारिक प्रस्ताव या बातचीत शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कोई आधिकारिक प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है, और विभाजन

के मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सुप्रिया सुळे ने कहा कि चर्चा केवल प्रत्येक वार्ड के स्तर पर राजनीतिक समीकरणों को देख कर हो रही है, और विस्तृत निर्णय महाविकास आघाड़ी (MVA) के सहयोगी दलों—विशेषकर कांग्रेस और शिवसेना (UBT)—के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वे एक संयुक्त मोर्चे में चुनाव लड़ें ताकि राजनीतिक समन्वय बना रहे।

सुळे ने यह भी कहा कि पार्टी का लक्ष्य पुणे के प्रमुख मुद्दों जैसे यातायात व्यवस्थापन, जल आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण और बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर केन्द्रित रहेगा, और निर्णय पुणे के हित में ही लिए जाएंगे। उनके बयान से स्पष्ट होता है कि फिलहाल दोनों NCP गुटों के बीच कोई निर्णायक तालमेल नहीं हुआ है, लेकिन आयामी कवायद और बातचीत जारी है।





नांदेड में कपास तोड़ रही महिला पर भालू का हमला, बच्चे की सूझबूझ से बची जान



नांदेड (माहूर), 24 दिसंबर 2025: नांदेड जिले के बामनगुडा (गोंडखेडी) क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक भालू ने कपास तोड़ रही लता सुरेश तोडसाम (35) पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जखमी हो गई। घटना तब हुई जब वह अपने बेटे और एक मजदूर के साथ खेत में काम कर रही थीं। भालू ने उनके चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोट पहुंचाई। घटना को देख कर उनके छोटे बेटे और मजदूरों ने जोरदार चीख-पुकार की, जिससे भालू डरकर भाग गया और महिला की जान बच गई।

जखमी महिला को तुरंत सिंदखेड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर माहूर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से गंभीर स्थितियों के कारण उन्हें आगे यवतमाळ शासकीय अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने भालू के पैरों के निशान व अन्य साक्ष्य एकत्रित कर पंचनामा तैयार किया है और गाँव वालों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे खतरनाक हमले न हों।

नांदेड में NCP नेता जीवन घोरे पाटील का अपहरण और बेरहम पिटाई, वित्तीय विवाद के आरोप में राजनीति गरमाई

नांदेड, 23 दिसंबर 2025: महाराष्ट्र के नांदेड जिले से एक गंभीर राजनीतिक एवं आपराधिक मामला सामने आया है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश महासचिव जीवन पाटील घोरे का कथित रूप से अपहरण कर मारपीट की गई और बाद में उन्हें अज्ञात स्थान पर छोड़ा गया। घटना की जानकारी सीसीटीवी फुटेज और पुलिस शिकायत के आधार पर मिली है।



घटना 22 दिसंबर को दोपहर लगभग पूर्वाह्न में उस समय हुई जब घोरे अपनी टोयोटा इनोव्हा कार में नांदेड ग्रामीण इलाके के ज्ञानेश्वर नगर की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आई महिंद्रा स्कॉर्पियो ने घोरे की कार को अचानक रोक दिया और कुछ आरोपियों ने उन्हें जबरदस्ती उस वाहन में ठूसकर ले लिया।

इसके बाद वे उन्हें कुछ दूरी तक ले गए और कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। कुछ समय बाद घोरे को किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया गया, जहाँ से वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई। घोरे ने शिकायत में आरोप लगाया कि इस पूरे घटित अपराध के पीछे राजनीतिक और

आर्थिक मतभेद हैं। उन्होंने वर्तमान नांदेड विधायक प्रतापराव पाटील चिखलीकर और पूर्व विधायक मोहनराव मारोत्रांव हमबर्डे पर इस योजना को अंजाम देने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है। घोरे का कहना है कि उन्हें यह चेतावनी भी दी गई कि वे “भविष्य के मंत्री चिखलीकर के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें”

और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पुलिस ने इस मामले में अभी तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम शुभम दत्ता सुनेवाड, राहुल मारोती दसारवाड, कौस्तुभ राणवीर, विवेक सूर्यवंशी, माधव वाघमारे, मोहम्मद अफरोज फकीर और देवनाद भोळे रहे हैं। तीन अभियुक्तों के पहले से आपराधिक रिकॉर्ड होने की भी पुष्टि पुलिस ने की है। घटना के बाद नांदेड में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और घोरे के समर्थकों ने बंद की घोषणा की है। घायल घोरे वर्तमान में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और उन्होंने राज्य नेतृत्व से नांदेड में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया है।



भाजपा ने नांदेड मनपा चुनाव की कमान मजबूत की, सांसद डॉ. अजित गोपछडे बने सह-प्रभारी

नांदेड (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी ने नांदेड महानगरपालिका चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को और धार देते हुए सांसद डॉ. अजित माधवराव गोपछडे की मनपा चुनाव सह-प्रभारी के रूप में नियुक्ति की है। यह नियुक्ति भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक रविंद्र चव्हाण द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से की गई है। इससे नांदेड महापालिका पर सत्ता

हासिल करने के भाजपा के दृढ़ संकल्प को बल मिला है। डॉ. अजित गोपछडे को सह-प्रभारी बनाए जाने से पार्टी की चुनावी मशीनरी और अधिक सशक्त हुई है। इससे पहले राज्य की मंत्री पंकजाताई मुंडे को मनपा चुनाव प्रभारी तथा सांसद अशोकराव चव्हाण को महानगर चुनाव प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। ऐसे में भाजपा ने अनुभवी और प्रभावी नेतृत्व की टीम खड़ी कर

दी है। संगठनात्मक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और जनता से सीधे संवाद की पहचान रखने वाले सांसद डॉ. गोपछडे के नेतृत्व में कुंडलवाडी में भाजपा की हाल ही में उल्लेखनीय जीत मिली है। उनकी नियुक्ति से नांदेड में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और आगामी मनपा चुनाव में पार्टी को मजबूत बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

देगलूर नगरपालिका पर खतगावकर के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस की बड़ी जीत



संवाददाता |

नांदेड जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका देगलूर में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ऐतिहासिक विजय दर्ज की है। यह चुनाव पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद भास्करराव पाटील खतगावकर के सशक्त नेतृत्व में लड़ा गया। खतगावकर ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का उपयोग करते हुए सभी समाजों, जातियों और धर्मों के मतदाताओं को साथ लेकर विजय की मजबूत रणनीति तैयार की, जिसका परिणाम राष्ट्रवादी के रूप में सामने आया।

नांदेड जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुल 3 नगराध्यक्ष और 71 नगरसेवक निर्वाचित

हुए हैं, जिससे पार्टी जिले में दूसरे स्थान पर रही है। देगलूर क्षेत्र में खतगावकर के कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज और व्यापक जनसंपर्क का बड़ा लाभ पार्टी को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, नवाब मलिक, रुपाली चाकणकर, नांदेड जिले के वरिष्ठ नेता विधायक प्रताप पाटील चिखलीकर सहित वरिष्ठ नेताओं की जाहीर सभाएं हुईं। प्रभागवार बैठकों और संगठित प्रचार के चलते देगलूर नगरपालिका पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का विजयी परचम लहराया।



भोकर में AIMIM की एंट्री से बदला राजनीतिक समीकरण

भोकर संवाददाता, बालाजी घोरे पाटील | भोकर नगर परिषद चुनाव में इस बार राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। वर्षों से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले भोकर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल कर नगर परिषद पर कब्जा जमा लिया। इस बदलाव में AIMIM की एंट्री को निर्णायक माना जा रहा है, जिससे कांग्रेस की पारंपरिक

मतबैंक में बड़ी सेंध लगी।

चुनाव से पहले अशोक राव चव्हाण के पार्टी परिवर्तन के बाद कांग्रेस कमजोर पड़ गई थी। भाजपा ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उम्मीदवार चयन से लेकर बूथ स्तर तक सटीक रणनीति अपनाई। कांग्रेस ने भी वापसी की कोशिश की, लेकिन आपसी मतभेद, सहयोगी दलों से दूरी और अंतिम चरण में मतों के बिखराव ने पार्टी को

नुकसान पहुंचाया।

नगराध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, वंचित और AIMIM सहित कई दल मैदान में थे। मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस माना जा रहा था, लेकिन मत विभाजन के चलते यह भाजपा बनाम AIMIM बन गया। नतीजतन कांग्रेस तीसरे स्थान पर सिमट गई और भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

नांदेड में हार-जीत का नजारा: दो उम्मीदवार 1 और 2 मतों के अंतर से निर्वाचित — रोमांचक निकट मुकाबले के साथ स्थानीय चुनाव परिणाम



चर्चा का विषय बन गया है।

नांदेड (23 दिसंबर 2025): नांदेड जिले में 21 दिसंबर को सम्पन्न स्थानीय निकाय (नगरपरिषद और नगरपंचायत) चुनावों के परिणाम सोमवार को घोषित हुए, जिनमें कई सीटों पर बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले। इन परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक-एक वोट भी निर्णायक हो सकता है, क्योंकि कुछ उम्मीदवार केवल 1 या 2 मतों के अंतर से जीतकर निर्वाचित हुए हैं।

मुख्य नगरपरिषद के एक प्रभाग में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी प्रेमला गोपीनाथ पांचाळ अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से केवल 1 वोट अधिक पाकर जीत गईं। उनके मुकाबले में कांग्रेस की उम्मीदवार मोहम्मद शाहिदा मो. शफी मात्र एक मत के अंतर से हार गईं, जिससे यह परिणाम जिले भर में

इसी तरह किनवट नगरपरिषद के एक अन्य प्रभाग (क्रमांक 3 ब) में उबाठा शिवसेना के श्रीराम नारायणराव नेम्मानेवार को 632 वोट मिले, जबकि भाजपा के फिरोज बाबू तवर को 630 वोट, यानी केवल 2 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस नज़दीकी मुकाबले ने भी मतदाताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया।

इन अत्यंत समीप परिणामों ने मतदाताओं के बीच मतदान की महत्ता को उजागर किया, यह दर्शाता है कि हर एक वोट का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्तर पर निकले ये नतीजे यह भी प्रमाणित करते हैं कि चुनावों में मतगणना के अंतिम चरण तक परिणाम अनिश्चित रह सकते हैं और छोटी-छोटी मतसंख्या भी चुनावी परिणाम बदल सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे निकट परिणाम लोकतंत्र की सजीवता को दर्शाते हैं और मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे, क्योंकि नागरिक अब यह समझ रहे हैं कि उनका एक-एक वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता पर सख्ती, पहले अधीक्षक चखेंगे खाना

नांदेड। राज्य के शासकीय छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद सामाजिक न्याय विभाग ने कड़ा फैसला लिया है। नए शासन आदेश के अनुसार अब विद्यार्थियों को भोजन परोसने से पहले छात्रावास अधीक्षक (गृहपाल) द्वारा भोजन चखना अनिवार्य किया गया है। अधीक्षक की अनुमति के बाद ही छात्रों को भोजन दिया जाएगा।

सामाजिक न्याय विभाग के अधीन चल रहे छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और मात्रा को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। कई जगहों पर भोजन में कीड़े मिलने, खराब अनाज के उपयोग और भोजन कम पड़ने की शिकायतें सामने आई थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है।

सरकारी आदेश में छात्रावासों की रसोई और भोजन व्यवस्था को लेकर सख्त नियम तय किए गए हैं। रसोई कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन समय पर देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वेतन में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या ठेका रद्द किया जाएगा।

नांदेड जिले में इस शैक्षणिक वर्ष में 16 शासकीय छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 1,477 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। नए निर्णय के लागू होने से भोजन की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।



चंद्रकांत खैरे का तीव्र विरोध: रशीद मामू के शिवसेना में प्रवेश पर भिड़ा राजनीतिक माहौल

छत्रपती संभाजीनगर,: आगामी महापालिका चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) में कांग्रेस के पूर्व महापौर अब्दुल रशीद खान उर्फ रशीद मामू के पार्टी में शामिल होने पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। रशीद मामू और उनके साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में प्रवेश किया, जिसमें वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

हालाँकि, पार्टी के वरिष्ठ नेता और माजी सांसद चंद्रकांत खैरे ने इस प्रवेश का खुलकर विरोध किया है। खैरे ने कहा कि रशीद मामू को पार्टी में शामिल करना गलत फैसला है और उन्हें किसी भी स्थिति में उम्मीदवार

नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने रशीद मामू को सीधे कहा, “तुम्हें मेरा विरोध है, यदि तुम्हें टिकट दिया गया तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।”

चंद्रकांत खैरे ने आरोप लगाया कि 1986 में रशीद मामू का दंगों में हिरासत का इतिहास रहा है और ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना शिवसेना के पारंपरिक मूल्यों और हिंदुत्व मतदाताओं की भावनाओं के विपरीत है। खैरे के मुताबिक इससे करीब 50,000 हिंदू वोटों का नुकसान हो सकता है।

इस विवाद में खैरे ने यह तक कहा कि रशीद मामू के स्थान पर एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को

उम्मीदवार बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे पार्टी की स्थिरता और चुनावी संभावनाएँ बेहतर रहें।

वहीं, अंबादास दानवे ने स्पष्ट किया कि निर्णय पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का होगा और वरिष्ठ नेताओं की राय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में जो भी शामिल होंगे, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यह घटना शिवसेना के आंतरिक मतभेदों और आगामी चुनाव रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में बढ़ती बहस का कारण बनी हुई है।

